



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1935 (श0)

(सं0 पटना 756)

पटना, मंगलवार, 1 अक्टूबर 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

25 सितम्बर 2013

सं0 22/नि0सि0(पट0)-03-06/2012/1178—श्री ईश्वर सहाय राम, (आई0 डी0-4570) तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध दिनांक 12.4.05 से दिनांक 6.12.05 तक कार्य से अनुपस्थित रहने के संबंध में प्रपत्र-“क”में निम्न आरोप गठित कर विभागीय पत्रांक 994 दिनांक 12.9.12 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी:-

आरोप सं0-1 ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-1805 दिनांक 11.4.05 द्वारा इनकी सेवा पैतृक विभाग (जल संसाधन विभाग) में वापस की गयी। उक्त आदेश का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया। इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद सं0-11454/05 दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक 6.12.05 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में इन्होंने दिनांक 7.12.05 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया है। इनके द्वारा ग्रामीण विकास विभाग का पद त्याग करने का प्रभार प्रतिवेदन दिनांक 10.6.06 को विभाग में समर्पित किया गया है, जिसमें प्रभार सौंपने की तिथि 6.12.06 अंकित है और तिथि 6.12.05 में हस्ताक्षरित है, जो स्पष्टता गलत है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले की तिथि को ही इन्होंने अररिया कार्यालय प्रभार त्याग किया है जबकि फैसले की सत्यापित प्रति माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 9.12.05 को हस्ताक्षरित है, स्पष्टतः इनके द्वारा समर्पित किया गया प्रभार प्रतिवेदन प्रपत्र-202 में बैंक डेटिंग कर हस्ताक्षर किया गया है, जो इनकी गलत मंशा का द्योतक है। प्रभार सौंपने के बाद उक्त कार्यालय से प्रभार प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है, जो इनके मामले में नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से इनके द्वारा विभाग को धोखा देने की नियत से जालसाजी कर कागजात तैयार किया गया है। इस गलत कृत्य और जालसाजी के लिए ये प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये हैं।

आरोप सं0-2 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उक्त विभाग में इनकी सेवा दिनांक 16.10.04 से दिनांक 11.4.05 तक का ही जॉच प्रतिवेदन दिया गया है एवं स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 12.4.05 से दिनांक 6.12.05 तक ये ग्रामीण विकास विभाग में नहीं रहे हैं, जो इनकी स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति को दर्शाता है, जिसके लिए भी ये प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये हैं।

उक्त आरोप के आलोक में श्री राम, कार्यपालक अभियन्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्य अंकित किया गया है:-

ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना सं०-1805 दिनांक 11.4.05 द्वारा अकारण असामयिक उनकी सेवा पैतृक विभाग (जल संसाधन विभाग) में वापस कर दी गई, जिसके विरुद्ध वे माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी० डब्लू० जे० सी० सं०-11454/05 दायर किये। उक्त वाद में दिनांक 6.12.05 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय पारित किया गया। उक्त न्याय निर्णय की प्रत्यक्षा में पदस्थापन अवधि दिनांक 14.9.04 से 6.12.05 तक बितायी गई अवधि है। इसलिये अनर्गल आदेश के क्रम में जल संसाधन विभाग में योगदान नहीं किया। प्रभार प्रतिवेदन 202 में दिनांक 6.12.06 अग्रिम वर्ष अंकित होना मानवीय भूल है। मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता का हस्ताक्षर दिनांक 6.12.05 स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है।

श्री राम, कार्यपालक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राम की सेवा तीन वर्षों के लिए ग्रामीण विकास विभाग में सौंपी गई थी, परन्तु उनका कार्यकलाप सही नहीं रहने के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनहित में उनकी सेवा ग्रामीण विकास विभाग पैतृक विभाग (जल संसाधन विभाग) में वापस कर दिया गया जिसके विरुद्ध वे माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी० डब्लू० जे० सी० सं०-11454/05 दायर किये तथा दिनांक 6.12.05 तक न्याय निर्णय आने की प्रतीक्षा में विभाग से अनुपस्थित रहे जबकि उन्हें सरकारी आदेश का अनुपालन करते हुए स-समय प्रभार सौंपना चाहिये था।

वर्णित स्थिति में श्री ईश्वर सहाय राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग सम्प्रति उप निदेशक, जल विज्ञान प्रमण्डल (मध्य) पटना के विरुद्ध सरकारी आदेश का अनुपालन स-समय नहीं करने, समय पर प्रभार नहीं सौंपने तथा दिनांक 12.4.05 से 6.12.05 तक स्वेच्छापूर्वक कार्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया:-

1. दिनांक 12.4.05 से 6.12.05 तक कार्य नहीं तो वेतन नहीं। परन्तु उक्त अवधि को पेंशन प्रदायी माना जायेगा।

2. आदेश निर्गत की तिथि से दो वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री ईश्वर सहाय राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग सम्प्रति उप निदेशक, जल विज्ञान प्रमण्डल (मध्य) पटना को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है।

1. दिनांक 12.4.05 से 6.12.05 तक कार्य नहीं तो वेतन नहीं। परन्तु उक्त अवधि को पेंशन प्रदायी माना जायेगा।

2. आदेश निर्गत की तिथि से दो वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 756-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>